1. प्रस्तावना

ernkrk Hkkb;k vkj cguk]

आगामी 3, 15, एवं 23 फरवरी 2005 वे दिन हैं जो झारखण्ड के भविष्य का फैसला करेंगे । जनता अपने मतों से निर्वाचित पहली सरकार का गठन करेगी । देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें झारखण्ड राज्य नहीं दिया होता तो आज तक हम राजद के शोषण और अराजकता के शिकार बने रहते। सच में, झारखण्ड की पौने तीन करोड़ जनता भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के सपूत श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है । 15 नवम्बर 2000 का दिन, भारत के मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखण्ड के उदय के साथ ही ऐतिहासिक और अमर हो गया । पौने तीन करोड़ झारखण्डवासियों का सपना साकार हुआ ।

कौन नहीं जानता कि झारखण्ड राज्य के लिए एक लंबा आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने तो सदैव फूट डाल कर आंदोलनकारियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की । जब 'झारखण्ड', राज्य बनने की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा था जब राजद और कांग्रेस झारखण्ड की भ्रूण हत्या करने में लगी थी । पौने तीन करोड़ झारखण्डवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली राजद सुप्रीमो ने यहां तक कहा था कि "झारखण्ड मेरी लाश पर बनेगा" । परन्तु जीत जनता की भावनाओं की हुई ।

Qjojh 2005 e: >kj[kM d ernkrkvk dk fo/kkulHkk puko e: nk Vd Qlyk yuk gkxk। उनके समक्ष एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने झारखंड राज्य का उपहार दिया । नवसृजित राज्य झारखंड को पल्लवित पुष्पित करने, विकास की दिशा में ले जाने और विकसित राज्यों के समकक्ष झारखंड को लाने का अथक प्रयास किया । दूसरी ओर अलग राज्य गठन के आंदोलन को असफल करने, जनआंदोलन की आकांक्षा की सौदेबाजी करने वाले, हिंसा अराजकता और सामाजिक तानाबाना को छिन्न–भिन्न करने में महारत हासिल करने वाले लोगों का जमावड़ा है । अभी केन्द्र में यूपीए की ऐसी सरकार है जिसने प्रधानमंत्री तक के पद का अवमूल्यन तथा शक्ति–क्षरण का अजीब उदाहरण प्रस्तुत किया है।

दागी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल रखना, कम्युनिस्ट पार्टियों के ब्लैक मेलिंग, राष्ट्रीय मानकों के साथ छेड़छाड़, आंतरिक सुरक्षा के खतरों के प्रति लापरवाही, सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा में कमी, अर्थव्यवस्था की गति में कमी, गरीब किसानों और बुनकरों की समस्या के प्रति लापरवाही, देशभक्तों का अपमान तथा आम आदमी से किये गए कांग्रेसी वायदों के खोखलेपन के कारण केन्द्र की यूपीए सरकार से देशवासियों का मोह भंग हो चुका है और केन्द्र की यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण चीनी, डीजल, गूड़ तथा किरासन जैसे रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बेताहाशा वृद्धि से गरीबों की कमर टूट चुकी है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है ।

मतदाता भाईयों और बहनों ! आपको यह जानने का हक है और जानना भी चाहिए कि झारखंड बनने के पूर्व तक झारखंड की क्या स्थिति थी ? पिछले चार वर्षों में हम कहाँ तक पहुँचे ? आने वाले पाँच वर्षों में हमारा लक्ष्य क्या है ?

जनता की भावनाओं को भाजपानीत तत्कालीन एनडीए सरकार ने मूर्तरूप दिया। भाजपा, जनता दल(यू), एवं कुछ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से झारखण्ड में भाजपा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ । गठित सरकार के बाद आज मौका आया है कि आप झारखण्ड में अपने मतों से पहली निर्वाचित सरकार बनायें । हम फरवरी 2005 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पुनः आपके समक्ष पूर्व का लेखा–जोखा और भविष्य के संकल्पों के साथ आ रहे हैं । हमें विश्वास है कि जनतंत्र की अदालत में भाजपा को आपके द्वारा न्याय मिलेगा । आपका न्याय ईश्वर का प्रसाद मानकर हम शिरोधार्य करेंगे ।

¼j?kqoj nkl½
अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
झारखण्ड प्रदेश

2. विरासत में मिली बेड़ियाँ

झारखंड नव राज्य बनने के पहले बिहार का ही हिस्सा था । बिहार में गत 15 वर्षों से राजद (लालू) की सरकार है । यानि झारखंड में गत 11 वर्षों तक लालू यादव+राबड़ी देवी की ही सरकार थी । ये दोनों पति– पत्नी ही बिहार+झारखंड के मुख्यमंत्री थे । पूरा झारखंड समस्याओं से घिरा हुआ था । उग्रवाद से प्रभावित अपराध क्षेत्र, पिछड़ापन, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, विस्थापन, अशिक्षा, स्वास्थ्य – क्षेत्र की सेवायें शून्य, जर्जर आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली एवं पानी का घोर अभाव, कृषि उत्पादन में कमी, सिंचाई सुविधा का भयंकर अभाव और खजाना बिल्कुल खाली । गत 11 वर्षों में बिहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बाद भी राजद+कांग्रेस+झामुमो ने सजाने–संवारने के बजाय झारखण्ड की प्राकृतिक संपदा को नोंच–खसोट कर पूरी तरह लूटा ।

tc geus lEgkyk rc gkykr ,sls Fks %&

- राज्य में विकास की वृद्धि दर थम गयी थी ।
- राज्य की 61 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी ।
- उग्रवाद के साथ–साथ अपराधियों का अड्डा बना गया था झारखण्ड ।
- राज्य में औद्योगिक विकास की दशा ऋणात्मक थी ।
- राज्य की कोई उद्योग नीति नहीं थी ।
- मध्यम एवं लघु उद्योग पूरी तरह ठप हो गए थे ।
- शिक्षा के क्षेत्र में तो अधिकांश स्थानों में स्कूल के लिए भवन ही नहीं थे ।
- राज्य में साक्षरता दर मात्र 51 प्रतिशत थी ।
- 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे ।
- आजादी के 57 वर्षों के बाद भी झारखण्ड का बड़ा हिस्सा मलेरिया, कुष्ठ एवं टीबी जैसे रोगों से ग्रस्त था ।
- केन्द्र से प्राप्त करोड़ों के अनुदान जो संविधान की धारा 175(1) के अंतर्गत आदिवासियों के विकास लिए मिलता था, उसका उपयोग ही नहीं हुआ ।

- सड़क और यातायात की सुविधा में घोर कमी थी।
- पुल–पुलिया के अभाव में प्रखंड से जिला मुख्यालय का सम्पर्क नहीं सा रहता था ।
- बिजली की व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी । 85 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं थी ।
- रेल सुविधाओं का घोर अभाव । हजारीबाग और दुमका जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी रेल सेवा से वंचित थी।
- शुद्ध पेयजल भी मुहैया नहीं होता था ।
- तकनीकी सुविधाओं और आधुनिक अस्त्र–शस्त्र के अभाव में पूरे राज्य में पुलिस का मनोबल निरंतर गिरता रहा ।
- विज्ञान और टेक्नॉलोजी (तकनीकी), सूचना तथा औद्योगिक के क्षेत्र में झारखंड पूरी तरह अभिज्ञ और अछूता था ।
- पर्यटन के स्थानों से भरपूर होने के बाद भी झारखंड राज्य में पर्यटन विकास का अस्तित्व नहीं था।
- पर्वतीय और वन भूमि बहुल राज्य होने के बाद भी वनों का क्षेत्रफल सिमट कर 15 से 20 फीसदी पर रह गया।
- शिशु मृत्यु दर, कुपोषण ग्रस्त बच्चों और महिलाओं की संख्या अधिक थी ।
- प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अभाव था । भ्रष्टाचार का बोलबाला था ।

संक्षेप में कहा जाए तो झारखंड के पास सब कुछ होने के बाद भी, जनता को कुछ नहीं दिया गया । झामुमो और कांग्रेस ने राजद को समर्थन देकर संयुक्त बिहार को चौपट करने का उसे लाईसेंस दे दिया। इसके साथ झारखंड को भी उनके द्वारा सत्यानाश के कगार पर ला दिया गया।

हमने गत चार वर्षों में भारत में नवसृजित झारखंड राज्य को नवविकसित बनाने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठाये। भविष्य में झारखंड भारत का सर्वाधिक विकसित और आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बने, इसके लिए भाजपा ने भावी संकल्प

लिया है। उन्हीं संकल्पों को हम आपके बीच विधान सभा चुनाव में रख रहे हैं। हम विश्वास दिलाते है हमारे इस घोषणा–पत्र का एक–एक शब्द,हमारे लिए गीता के मंत्रों की तरह पवित्र और करणीय हैं। घोषणा पत्र के एक–एक शब्द को हम सार्थक करेंगें। आप हमें पुनः सरकार बनाने और सेवा करने का मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का मौका नही देंगें।

3. नहीं होने देगें झारखण्ड को दुर्लक्ष्य
भाजपा के भावी संकल्प और लक्ष्य :-

df"k gekjk thou vkj d"kd vUunkrk gA

- कृषि को m|kx dk ntk प्रदान करना।
- किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर किसानों को .ऋण की सुविधा प्राप्त कराना ।
- किसानों को उसके फसल का उचित समर्थन मूल्य दिलाने की गारंटी ।
- राज्य के बीच गुणन प्रक्षेत्रों द्वारा उन्नत बीज उत्पादन कर राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ।
- कृषि उत्पादकता बढाने के लिए राज्य के वर्षा आधारित क्षेत्रों में जलछाजन विकास कार्यक्रम को व्यापक बनाना ।
- फसल, सब्जी एवं फल का विकास करने हेतु ^,xk ,Dl ikV tku* की स्थापना ।
- उद्यान फसलों का आच्छादन क्षेत्र बढाने तथा कृषि को व्यवसायीकरण प्रणाली से सम्बद्ध कराना है।
- पुष्प कृषि को बढ़ावा । औषद्यीय पौधों तथा जड़ी–बूटियों के उत्पादन को बढ़ाना ।
- राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास कार्यो को प्रोत्साहित कर दलहन एवं तेलहन फसलों का उत्पादन बढाना ।
- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ctV e 60 ifr'kr dk vkoVuA
- मधुमक्खी पालन का विकास ।

- झारखण्ड के 31 हजार किसानों का खतियान बिहार सरकार की तिजोड़ी में बंद था। भाजपा सरकार ने अपने चौथे स्थापना दिवस पर घोषणा की, कि सभी किसानों के खतियान वापस कर उनका ऋण भी माफ करेंगे।
- उन्नत कृषकों को पुरस्कृत करने की योजना । राज्य में व्यापक स्तर पर Qly chek ;kstuk लागू करना ।
- कृषि शिक्षा, शोध एवं विकास के क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ।
- कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने हेतु अधिक से अधिक जल स्त्रोतों का दोहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- ^fdlku cd* का प्रावधान । प्रत्येक जिलों में ^vUunkrk Hkou* ।
- सबको भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधायें उपलब्ध कराना।
- y.M fjdkM dk v|ru किया जाएगा ।
- विभिन्न काश्तकारी अधिनियमों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा ।
- Hkfe dk ,d lkl/ku ekudj उसके विकास के लिए पूंजी निवेश किया जाएगा ।
- जोत के घटते आकार की समस्या का समाधान कर जमीन की उत्पादकता बढ़ायी जाएगी ।

पंचायती राज : ग्राम स्वराज से सुराज तक :-

- पंचायत निर्वाचन की सभी तैयारियाँ पूर्ण। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
- झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बना लिया गया ।
- इस अधिनियम के तहत निर्वाचन नियमावली तैयार, vily 2005 rd pquko ।
- राज्य के कुल 32,615 गांवों में 3765 ग्राम पंचायतों में शीघ्र चुनाव ।
- राज्य में कुल 299 पंचायत समिति एवं 22 जिला परिषद का गठन कुल 49794 जन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर प्रशासन में भागीदारी निभायेंगे ।

- lkekftd lejlrk ,o vkfFkd fo"kerk nij dju dk ldYi A
- पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन का निर्माण । हर ब्लाक प्रखंड में ''पशु चिकित्सिालय'' ।
- ^iip ije'oj* dh Hkkouk dk egRo दिया जाएगा । पंचायत व्यवस्था को सर्वाधिक महत्व ।
- पंचायत को ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बनाया जाएगा ।
- अगले दो साल में राज्य की हर पंचायत नेट से जोड़ी जाएगी। lHkh xkoka e VyhQku की सुविधा तथा आई.टी.पार्क।

अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लिए :-

- vUui.kk ;ktuk ¼ ikp :i;s e Hkjiv nky&HkkrA
- iR;d ifjokj d ,d lnL; dk futh {k=k e ukdjhA
- रोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण सुलभ । कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन।
- नौकरियों मे प्राथमिकता–vkfne tutkfr d Lukrdk dk vfuok;l :i l ljdkjh ukdjh A
- उच्चशिक्षा हेतु विदेश जाने के लिए राज्य सरकार सुविधा मुहैया करायेगी।
- मजदूरों को रोजगार गारंटी से जोड़ना ।
- सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाकर उन्हें सशक्त बनाने की योजनाओं पर अमलीकरण ।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को rhu :i;s fdyk pkoy और nk :i;s fdyk xgq मुहैया कराया जाएगा ।
- पहाड़ी जनजाति के छात्रों के लिए fo'k"k 0;olkf;d ¼Hkkd'kuy½ f'k{kk योजना। jkT; e ek= 25 iSls ifrfdyk ued ।
- झारखण्ड के आदिवासी एवं vkfne tutkfr dh lkLdfrd fojklr dh j{kk एवं उनका विस्तार।

महिला सशक्तीकरण :-

- jktdh; efgyk dk"k की स्थापना ।
- महिला स्वैच्छिक संगठनों (एन. जी. ओ.) को भरपूर सहायता ।
- efgyk ^Lon'kh ckTkj* प्रत्येक जिले में । efgyk 0;olkf;d if'k{k.k dk;Øe A
- महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा ।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं और उनके बच्चों के gYFk dkM शासकीय स्तर पर। स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क ।
- आंगनबाड़ी कार्यक्रम को गांव–गांव तक प्रभावी बनाने की योजना ।
- ,dy efgyk f'k{kd Ldy (सिर्फ बालिकाओं के लिए) स्वरोजगार हेतु कम व्याज पर ऋण ।
- efgyk mRihMu l efDr grq dM dkuu A महिला शिक्षा (अल्पावधि व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना)।
- महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय जनक यूनिटों का निर्माण ।
- dk;dkjh efgyk vkokl एवं o)k vkJe की स्थापना ।
- ग्रामीण महिलाओं को /kvkjfgr pYg उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- बच्चों को Ldy e ik"kkgkj की व्यवस्था की जाएगी ।
- अश्लील पोस्टर–चित्र पत्र–पत्रिकाओं एवं अश्लील कार्यक्रमों के सार्वजनिक प्रदर्शन को दंडनीय अपराध घोषित करना ।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए lyHk 'kkpky;k का निर्माण ।

शिक्षा :-

- शिक्षा को सुलभ और एक समान बनाने का प्रावधान ।
- lof'k{kk vfHk;ku को बढ़ावा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा निःशुल्क एवं आवश्यक करने की योजना।
- प्रत्येक जिलों में एक अंगीभूत महिला महाविद्यालय । एकल विद्यालय प्रत्येक गाँव में ।
- प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन प्राथमिक विद्यालय, दो माध्यमिक विद्यालय की स्थापना ।
- उच्च तकनीक पर आधारित 'कम्प्यूटर शिक्षा, सभी विद्यालयों में आवश्यक foodkun dh t;rh ।
- 12 tuojh dk ;ok fnol मनाने का निर्णय । i=dkfjrk ,o tulpkj fo'ofo|ky; की स्थापना।
- तकनीकी एवं उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों का निर्माण जिससे प्रतिभा पलायन रूके ।
- शिक्षकों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर । स्कूल भवनों का निर्माण द्रुत गति से ।
- मेधावी छात्रों को छात्रवृति । अजा–अजजा छात्रों की छात्रवृति में वृद्धि।
- ckfydkvk dk fu%'kYd f'k{kk A विकलांग छात्रों/छात्राओं की छात्रवृति में वृद्धि ।
- मूक बधिर एवं नेत्रहीन छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण ।
- प्राथमिक शिक्षा हेतु, जनसंख्या की बहुलता के आधार पर चिन्हित स्थान विशेष में वर्ष प्रथम वर्ग से राष्ट्रभाषा हिन्दी के अतिरिक्त संताली, बंगला, उड़िया, कुड़ख, हो, मुण्डारी, नागपुरी, खरिया, खोरठा, अंगिका भोजपुरी, मैथिली एवं कुरमाली में पठन पाठन की निश्चित व्यवस्था।

पर्यटन :-

- राज्य के पर्यटन को उद्योग का दर्जा ।
- पर्यटकों का आकर्षित करने हेतु राज्य के i;Vu LFkyk dk fodkl करना ।
- राज्य के सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को देश विदेश में प्रचारित एवं प्रसारित कर यहां के पर्यटन को विश्व स्तरीय ऊंचाई पर ले जाने की योजना ।
- धार्मिक स्थलेां का विकास एवं पर्यटन स्थलों के रूप में उसे विकसित करना।
- पर्यटन स्थानों के रख रखाव से स्थानीय नागरिकों को जोड़ना तथा व्यापक परिवहन व्यवस्था ।

छह सौ करोड़ की योजना

- मधुबन एवं पारसनाथ जी की जैनियों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों के विकास पर अमल।
- ljk;dyk e NÅ egkRlo का आयोजन ।

युवा एवं खेल नीति :-

le) ;ok & le) çn'k
l'kDr ;ok & l'kDr çn'k

- हमारे युवा परिवार, गांव, इलाके और समुदाय की शक्ति हैं। युवा हमारे प्रदेश का अत्यंत आदर्शवादी, प्रेरणादायी और उर्जावान वर्ग है। आज झारखंड का युवा वर्ग भाजपा की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है और हम भी उन्हें उतनी ही अधिक आशा और विश्वास से देख रहे हैं कि वे 21 वीं शताब्दी में झारखंड के उत्तराधिकारी हों।
- भाजपा मानती है कि उनमें सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने और प्रदेश को राष्ट्र के मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने की बड़ी भारी सृजनशील शक्ति है। हम उनके इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए एक सही वातावरण और सहायक नीतिगत ढ़ाँचा तैयार करने का वचन देते हैं।

- इस उदेश्य की पूर्ति के लिए हम एक ''युवा नीति'' को उद्घाटित करेंगे। जिसके कार्यान्वयन के लिए हमारी सरकार बजट में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करेगी। इसके कार्यान्वयन हेतु एक स्थायी ^^;qok vk;kx** dh LFkkiuk की जायेगी।

झारखंड पुनर्निर्माण वाहिनी का गठन करेगें। :–

- jkstxkj xkjUVh ;kstuk लागू करेगें – रोजगार मिलने के पूर्व तक योग्यतानुसार बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान होगा। युवाओं के स्वरोजगार हेतु एक वित्तीय संस्था का निमार्ण करेगें।

स्वतंत्र खेल विभाग :-

- राज्य के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु खेल के मैदान की व्यवस्था।
- खो–खो एवं कबड्डी –खेलों का विशेष प्रोत्साहन, राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का शिक्षण शुल्क माफ।
- विद्यालय एवं महाविद्यालयों में योग केन्द्रों की स्थापना । खेल विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।
- राज्य के पाँच–पाँच पुरूष एवं महिला खिलाड़ियों को jkT; dh ljdkjh] lsok esa lh/kh HkrhZA
- प्रतिवर्ष ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक पंचायत, प्रखंड, जिले और राज्य स्तर पर होगा।
- खेल संस्थाओं को हर प्रकार की नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जायेगा।

स्थास्थ्य :-

LokLF; gh lclsa cMk /ku gSA LoLFk efLr"d lsa gh fodkl lEHko gSA

- विद्यालयीय छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच।
- iPphl lkS fpfdRldksa dks fjDr inksa dks rRdky Hkjk tk;xkA
- आदिवासी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता तथा प्रोत्साहन ।

- जिला स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यापक सुधार, ग्रामीण धाइयों को प्रशिक्षित करने की व्यापक योजना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यापक सुधार, आर्युवैदिक चिकित्सा का विस्तार ।
- हौम्योपैथिक चिकित्सा को ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तार ।
- बड़े चिकित्सालयों एवं अस्पतालों का विस्तार निःशुल्क स्वास्थ्य् परामर्श केन्द्रों की स्थापना ।
- चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा हेतु व्यवस्था एवं अन्य चिकित्सा संबंधी कार्यों का विस्तार
- नीम – हकीम के नाम पर फर्जी दुकानदारी चलाने वालों पर रोक हेतु कानून।
- 'कैंसर एवं एड्स' की निरन्तर जाँच हेतु शासकीय व्यवस्था ।
- gsYFk dkMZ % गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को jkTkdh; gsYFk dkMZ A
- जनसंख्या नियन्त्रण के कारगर उपाय करना, ड्रग लाइसेन्स का सरलीकरण ।
- रिक्साचालक, टैम्पोचालक, ऑटोचालक होटल एवं दिहाड़ी मजदूरों की सामूहिक चिकित्सा की योजना।

परिवहन-

- स्कूल बसों के कर में छूट ।
- राज्य के प्रमुख प्रवेश स्थलों पर dEI;wVjkbt psd iksLV की व्यवस्था।
- ड्राईविंग लाइसेंस के लिए ^^LekVZ dkMZ ;kstuk** लागू की जाएगी।
- स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों एवं विकलागों शासकीय एवं प्राइवेट बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा।
- शहर भ्रमण हेतु विशेष बस का प्रावधान ।
- झारखंड राज्य परिवहन निगम की स्थापना ।

सड़क, एवं पेयजल

- सड़कों का जाल तो आजादी के बाद ही फैल जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हुआ । हम गांव–गांव तक सड़कों का जाल बिछायेंगे।
- ग्राम पंचायतों को प्रखंडों से और प्रखंडों को जिलों से जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता से बनाया जायेगा।
- पाँच हजार कि0 मी0 सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा।
- सड़कों का चौड़ीकरण तीव्र गति से तथा पेयजल संकट से निजात पाने हेतु गांव–गांव में नलकूप, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को नलकूपों का अनुदान ।
- कुंओं की सफाई ।
- प्रत्येक ग्रामपंचायत भवन के समीप नलकूप ।
- शहरों में पेयजल वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान ।

हर गांव को बिजली : अंधकार से मुक्ति का अभियान

- 'बिन बिजली सब सून'। बिजली बिना किसानी कार्य और उद्योग नहीं चल सकता उर्जा विकास के लिए बिजली बोर्ड का पुर्नगठन। 52 नये सब स्टेशनों का निमार्ण/तीन हजार छह सौ गांवों को इसी वर्ष बिजली पंहुचाने का संकल्प। 2007 तक समूचे झारखंड को अंधकार से मुक्त करने का संकल्प।
- सौर उर्जा, पवन उर्जा एवं जैविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए व्यापक स्तर पर संयंत्र लगाये जायेंगे साथ ही जो स्वयं लगायेंगे उन्हें अनुदान दिया जाएगा।
- घरेलू बिजली दरों की वृद्धि पर रोक ।
- पन बिजली परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाना ।
- राज्य को ऊर्जा के मामले में स्वावलम्बी बनाना ।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में निरन्तर समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

वन एवं पर्यावरण

- राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वनाच्छादन का प्रतिशत 29.61 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना।
- वन एवं वनों में रहने वाले दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाते हुए वनों का विकास करना।
- संताल परगना मे वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में अभयारण्य की स्थापना।
- वन रोपण का सघन अभियान चलाना।
- रैयती जमीन पर लगे पेड़ों पर j|;rk d ekfydkuk gd d fy, dkuu बनाकर उसे सरल बनाना।
- राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम एक स्थायी पौधशाला की स्थापना।
- राजकीय औषधीय वनस्पति पर्षद के तहत नाभिक केन्द्र के माध्यम से औषध ीय पेड़–पौधों के संरक्षण, विकास तथा विपणन की व्यवस्था करना
- सभी बड़ी इकाईयों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण, औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती से रोक।
- हर स्तर पर शिक्षा में ''पर्यावरण संरक्षण'' विषय जोड़ा गाएगा।
- सघन वृक्षारोपण के लिए पूंजी का आवंटन अधिक होगा।
- जल प्रदूषण रोकने के उपायों का कड़ाई से अनुपालन ।
- जन, जंगल, जानवर जल और जमीन आदि साधनों के सही उपयोग के लिए जमीनी पहल।
- नहर, तालाब एवं बांध के साथ–साथ सड़कों के किनारे सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा।

स्वायत्त शासी निकायों का गठन तथा विकास

- स्थानीय निकायों का गठन ।
- स्थानीय नगरीय निकायों का छह माह में निर्वाचन ।

- स्थानीय निकाओं के अन्तर्गत नगरीय विकास की वृहद् योजनाएं ।
- शहरी विकास संसाधनों तथा संरचनाओं पर विशेष ध्यान ।
- स्थानीय निकाय हेतु एक स्वतंत्र मंत्रालय और इसे स्वायत संस्था के रूप में विकसित करना।

कला एवं संस्कृति

- राज्य में बोली जानेवाली सभी भाषाओं की प्रतिष्ठा, vdknfe;k dh LFkkiuk] साहित्यकारों को प्रोत्साहन एवं सम्मान दिया जाएगा।
- जनजातीय कला एवं संगीत से जुड़े dykdkjk dk ithdr dj mUgs ikR lkfgr किया जाएगा।
- vkfnoklh yfyr dyk एवं lxhr vdkneh की स्थापना की जाएगी।
- नृत्य, चित्र, मूर्ति, साहित्य, लोकगीत, लोककला आदि क्षेत्रों में वर्षों से कार्यरत परन्तु अभी तक उपेक्षित पड़े कलाकरों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- समय–समय पर ललित कलाओं को समुन्नत करने के लिए प्रदर्शनियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- हस्त शिल्पियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें बैंकों से कम दर पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा।
- सभी जिला मुख्यालयों में कलाओं को उचित प्रोत्साहन एवं विकास के लिए lkLdfrd dUnk dh LFkkiuk की जाएगी।
- राज्य में एक dyk egkfo|ky; की स्थापना की जाएगी।

उद्योग एवं व्यवसाय :-

- त्वरित एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता हेतु अखिल भारतीय वित्त संस्थानों की पूँजी को झारखण्ड वित्त निगम के माध्यम से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में लगाने का ठोस बन्दोवस्त करना।
- बिहार से पिंड घुड़ाकर वित्त निगम की स्वतंत्र ईकाई का गठन ।

- जिला औद्योगिक केन्द्रों को सक्षम एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
- बड़े उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों के विकास की व्यवस्था सख्ती से लागू होगी।
- आलू प्याज जैसे अन्य कृषि उत्पादों पर विक्रीकर नहीं लगेगा। बिक्री कर का सरलीकरण किया जाएगा।
- इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कामर्स, लघु उद्यमी संघ तथा खुदरा विक्रेता संघ के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति गठित की जाएगी तथा उद्योग व्यवसाय की समृद्धि की दृष्टि से उनकी अनुशंसाओं के संदर्भ में उचित नीति एवं नियमों का निर्धारण किया जाएगा।
- 0;kolkf;d if'k{k.k dUnk की स्थापना की जाएगी।
- बाजार समिति के नियम और सरल बनाये जायेंगे।

श्रमिक कल्याण :-

- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, मौसमी मजूदरों, गृहनिर्माण में लगे मजदूरों, तथा मिट्टी मजदूरों आदि को न्यूनतम् मजदूरी दिलाने की गारंटी तथा इनके लिए 100 ifr'kr chek i'ku ;ktuk लागू की जाएगी।
- Je ekeyk dh rjjr fuiVkjk tk;xkA
- cky Jfedk d iuokl dh 0;oLFkk की जाएगी।
- श्रम कानून का पालन कठोरता से होगा
- बंधुआ मजदूरों की मुक्ति अभियान चलाया जायेगा।

गरीबी उन्मूलन :-

- सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं उपेक्षित तथा असहाय वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं का चयन कर समुचित रूप से उसका संपादन किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार की सभी कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभान्वित तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए सभी कार्यक्रमों को संख्ती से लागू किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची की शत प्रतिशत समीक्षा होगी। सही अर्थो में गरीब एवं छूटे हुए असमर्थ लोगों के नाम शामिल किये गायेंगे।
- गरीबों की आवासीय योजना का लाभ उचित व्यवक्तियों को दिलाया जाएगा।
- जनवितरण प्रणाली का लाभ गरीबों को सर्वाधिक मिले, इसकी व्यवस्था होगी।

अल्प संख्यक विकास :-

- अल्प संख्यक वर्गों को निर्माण और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु गंभीर, योजनाबद्ध और ठोस प्रयास किये जायेंगे।
- अल्प संख्यक शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों का स्तर सुधारने और उन्हें सामान्य शिक्षा के समरूप बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- सभी जिलों में पर्याप्त अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण ।
- मदरसा शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जायेगा और उन्हें आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ा जायेगा।
- अल्पसंख्यकों के विकास से सम्बंधित सरकारी एवं अल्पसरकारी संस्थाओं जैसे अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू अकादमी, उर्दू परामर्श समिति, झारखंड मदरसा बोर्ड, एवं वित्त निगम आदि बनाया जायेगा।
- साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण निर्मित कर दंगामुक्त समाज के निर्माण के लिए सार्थक प्रयास किये जायेंगे।

आवास सुविधायें :-

- आवास एक बुनियादी आवश्यकता है। धन के अभाव में लोग घर नही बना पाते। ''अपना घर'' तो हर व्यक्ति का सपना होता है। शहरों में तो बहुत से लोग सड़क किनारे रात काटने को विवश है। हमारा प्रयास होगा कि सबों का vkokl h; l fo/kk उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रतिवर्ष राज्य में 50 हजार नए मकान बनाये जायेंगे।

- लोकहित मे आवश्यकतानुसार आवास निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण तत्काल प्रचालित बाजार दर पर ही किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए आवासों एवं आवासीय कालनियों का तीव्र गति से निर्माण ।
- सरकारी गृह निर्माण वित्त निगम की स्थापना।
- सरकारी मंत्री या उच्च पदाधिकारियों के सरकारी आवास का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक नही होगा।

महत्वपूर्ण संकल्प :-

- l juk /kekoyEch tutkfr;k d fy, mudh vkcknh d vuikr e vkj{k.k rFkk lj{k.k dh 0;oLFkkA
- धर्मान्तरण पर रोक लगाने हेतु कानून बनेगा ।
- गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध। गौवंश की तस्करी पर रोक : गौ सेवा आयोग का गठन ।
- vkfnokl h /kkfed LFkyk dh lj{kk ,o lkUn;hdj.k ij fo'k"k /;ku A
- भूमिसुधार कानून तथा ^Hkfe cd* dh LFkkiuk ।
- संताल परगना में मेडिकल, इजीनियरिंग एवं कृषि विश्वविद्यालय के साथ–साथ nedk e mPpU;k;ky; d cp dh LFkkiuk ।
- आदर्श भरतीय गांव की कल्पना iR;d ftyk e fodkl dh lex ;ktuk को विकास नीति के तहत साकार करना ।
- राज्य में lLdr fo'ofo|ky; dh LFkkiukA

कांग्रेस आयी और मंहगाई लायी : हमारा प्रयास अपने स्तर पर रोकना होगा

- केन्द्र में यूपीए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में बनी है। कांग्रेस को राजद और झामुमों का भी समर्थन प्राप्त है। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि कुर्सी के

लिए केन्द्र में सभी दल एक साथ हैं। वहीं सभी कुर्सी के लिए एक दूसरे के विरूद्ध लड़ भी रहे हैं। लेकिन यूपीए के सभी घटक बढ़ती मंहगाई पर चुप्पी साधे हुए है। शक्कर 22 रूपये किलों बिक रहा है। गैस सिलेण्डर जो आज से सात माह पूर्व सहज रूप से सभी को मिल रहा था। आज वही यूपीए सरकार में सरेआम ब्लैक में बिकने लगी है। खाने की रोटी से लेकर डीजल, पेट्रोल एवं किरोसीन के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि भारत के आम नागरिक का जीना दुश्वार हो गया है। जबकि यूपीए की अगुवाई कर रही कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ'' पर सच्चाई तो यह है कि आम आदमी, कांग्रेस के द्वारा बढ़ाई जा रही कीमतों की मार से बुरी तरह कराह रही है ।

- हमारा प्रयत्न होगा कि हम अपने स्तर पर इन सभी वस्तुओं की दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगायें।

भ्रष्टाचार उन्मूलन और नियंत्रण

- आजादी के बाद कांग्रेस के कार्यालय से ही राजव्यापी भ्रष्टाचार का संपूर्ण देश में बोलबाला रहा। भ्रष्टाचार कांग्रेस एवं राजद के कार्यसंस्कृति का हिस्सा बन गया है। संयुक्त बिहार में यदि हिसाब लगायें तो अभी तक कांग्रेस और लालू–राबड़ी ने दस हजार करोड़ से ज्यादा की संपति लूटी है। आज भी दागी मंत्रियों की जमात कांग्रेस और राजद मे है। चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला तो हर जुबां पर है। हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
- पर्याप्त संख्या में fo'k"k vnkyrk dk xBu कर भ्रष्टाचार के लंबित मामलों में त्वरित ट्रायल की व्यवस्था करेंगे ताकि भ्रष्टाचारियों को दंड मिले।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निगरानी विभाग को सार्थक, सक्रिय, सक्षम और उत्तरदायी बनाया जायेगा।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए iz'kklu esa tuHkkxhnkjh बढ़ायी जायेगी।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए lkoZtfud dk;kZ dk lkoZtfud lfefr;ksa ls vkWfMV कराने की व्यवस्था की जायेगी।
- Hk"Vkpkj dh iz[kj tkudkjh nsus oky s ukxfjdksa dks iqjLd`r किया जायेगा और राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति दिया जायेगा।

उग्रवाद

- भारत महर्षि वाल्मीकि का देश है जो पहले 'रत्नाकर' कहलाते थे। वीहड़ जंगलों में लूटपाट करने वाले रत्नाकर के हृदय में विवेक का जब उदय हुआ तो वे रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। अतः उग्रवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें आजीविका से सम्बद्ध करने के लिए सरकार jRukdj ;kstuk चलायेगी ।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास की गति को तेज करना। उग्रवादी संगठनों से संवाद स्थापित करना। उग्रवाद के कारणभूत समस्याओं के निवारण की दिशा में गंभीरता से प्रयास करना।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन–जीवन की सुरक्षा तथा उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त पुलिस बलों की पर्याप्त व्यवस्था।
- उग्रवादी हिंसक गतिविधि में मारे जाने वाले राज्य के पुलिस एवं केन्द्रीय सुरक्षा कर्मियों को विशेष अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी।
- उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्यपर्ण नीति लागू करना।

रोजगार सृजन :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में cMh la[;k esa NksV&NksVs m|e स्थापित कर गरीब लोगों को सक्षम बनाना एवं उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।
- राज्य में कृषि योग्य जलवायु खनिज तथा मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग कर सघनता से jkstxkjksUeq[kh vkS|ksxhdj.k dks c<kok देना ।
- राज्य में अधिकतम पूँजी निवेश सुनिश्चत कर आर्थिक गतिविधियों को इस रूप में बढ़ावा जिससे LFkkuh; ykxksa dks jkstxkj मिल सके ।
- ekuo lalk/ku dks izeq[krk nsuk जिससे सभी सक्षम एवं योग्य व्यक्तियों को उनकी रूचि योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जा सके । इस हेतु {kerkvksa dh igpku dk ,d fe'ku dk :i nsukA

- पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर –इससें स्थानीय लोगों को जोडकर उन्हें अधिकाधिक रोजगार मुहैया करना।
- राज्य की संस्कृतिक विरासत खास कर अदिवासी एवं अन्य वर्ग समूहों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से dykdkjk dk jkstxkj मुहैया कराना।
- ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के मजबूत स्तम्भ गव्य विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन का विस्तार कर इसे ग्रामीण युवक/युवतियों की आजीविका का माध्यम बनाना। 'सहकारी दुग्ध उधोग' को प्रोत्साहित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना तथा उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निश्चित करना।
- राज्य में सीसम, सागवान, आम, कटहल एवं बांस आदि पर आधारित m|kxks ds ek/;e ls l{ke 0;fDr;ksa dks jkstxkj मुहैया कराना ।
- गरीब मजदूरों के लिए ^dk;Z ds cnys vukt ;kstuk* को प्रोत्साहन ।

4. एक नहीं अनेक जनहितकारी कदम ; कम समय में ज्यादा काम

lk>k ljdkj dh leL;kvksa vkSj lhekvksa ds ckotwn Hkktik ds usrRo okyh jkT; ljdkj us pkj o"kksZ esa ,d ugha vusd ,sls tufgr dkjh dk;ZØe fd;s gSa] ftl ij >kj[k.M dh ikWap rhu djksM+ turk Lo;a xoZ djrh A iwoZ eq[;ea=h ckcwyky ejk.Mh rFkk orZeku eq[;ea=h vtZqu eq.Mk dh vxqokbZ esa fujk'kk dh dkbZ NVh vkSj vk'kk & fo'okl dk l`tu gqvkA Hk;] Hkw[k] Hkz"Vkpkj ls la?k"kZ djrs gq, Hkz"Vkpkj ls >kj[k.M dks futkr fnykus dh igyh dksf'k'k dh x;h A

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः

eq[;ea=h dh vo/kkj.kk ^^cVh ijk;h jkT; dh Fkkrh** vc cVh ckst ugha

- पूरे देश में चर्चित झारखण्ड की vuwBh dU;knku ;kstuk।
- अब बेटियों की शादी में माता–पिता को अपना सब कुछ गिरवी रखना जरूरी नहीं।

- gtkjksa dU;kvksa dh lkewfgd 'kknh का ऐतिहासिक आयोजन।
- एक ही मंडप में हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को बराबर तरजीह देते हुए विविध रीति रिवाजों से शादियाँ सम्पन्न।
- शादी में संलग्न पंडित, मौलवी, पाहन, पादरी को भी मुख्यमंत्री द्वारा बेटी के बाप की हैसियत से सम्मानित किया गया।
- कन्यादान योजना का उद्देश्य महिला पुरूष की संख्या में आ रही असमानता को दूर करना है। झारखण्ड की यह बेमिसाल योजना पूरे jk"Vªh; Lrj ij pfpZr rFkk iz'kaflr हुई है।

कल्याण विभागीय योजनाओं की सफलता

- बस वितरण योजना से 5890 अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लाभान्वित।
- अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए 140 बसें वितरित करने का प्रावधान।
- पिछड़ी जातियों के तथा अल्पसंख्यक बेरोजगारों के लिए छोटी गाड़ी देने की योजना।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 240 छात्रावास का निर्माण प्रगति पर (100 से अधिक छात्रावास निर्मित)।
- अनुसूचित जनजाति के 25 युवकों को मुफ्त पायलट प्रशिक्षण।
- विरसा मुण्डा तकनीकी छात्रवृति योजना से 1035 छात्र लाभान्वित।
- अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृति योजना से राज्य के बाहर तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को 50 लाख की छात्रवृति।
- प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड़ रूपये की छात्रवृति।

हर गाँव में बिजली :-

- उर्जा के विकास के लिए बिजली बोर्ड का पुनर्गठन, राज्य गठन के बाद 52 नए सब स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति पर, अब तक दो हजार से अधिक नए गाँवों तक बिजली पहुँचाई गई तथा भारत सरकार के लोक उपक्रम राइटस ds }kjk ekpZ 2005 rd rhu gtkj Ng lkS vfrfjDr xkoksa rd fctyh igqapkus dk y{; fu/kkZfjrA

सिंचाई क्षमताओं का सृजन तथा वृद्धि :-

- राँची जिला में लतरातु, धन सिंह टोला योजना तथा गुमला जिला मे तपकरा, कतरी एवं कंसजोर जलाशय योजनाओं का कार्य सम्पन्न, देवघर एवं जामताड़ा जिला में अजय बराज योजना, सिंहभूम जिला में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत चांडिल मुख्य नहर तथा सोनुआ जलाशय योजना का कार्य सम्पन्न, राँची की सुरगी तथा दुमका की गुमानी बराज योजनायें सम्पन्न।
- इन परियोजनाओं के द्वारा 2.005 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 10.76 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता में वृद्धि का कार्य प्रगति पर।

सड़को की दशा बदली

- 1200 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण सम्पन्न ।
- एक हजार किलोमीटर सड़कों का पक्कीकरण सम्पन्न ।
- राज्य में छोटी सड़कों एवं पुल पुलियों का जाल बिछाया गया।

महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण :-

- दुमका–मसलिया पथ में मयुराक्षी नदी पर विजयपुर पुल। गोविन्दपुर–नारायणपुर–जामताड़ा पथ में करमदाहा पुल। पाकुड़–बड़हरवा पथ स्थित गोमानी नदी पर पुल। दुमका–कुंडहित पथ स्थित अजय नदी पर पुल। गांवा–सतगांवा पथ में तमुलिया व सकरी नदी पर पुल। चंद्रपुरा–बोकारों के बीच दामोदर नदी पर पुल। सिल्ली–बांता–रंगामाटी पथ पर राढ़ू, कांची डुमरा और सीतु पुल। पाकुड़–महेशपुर पथ स्थित बासुलिया नदी पर पुल एवं जुरदाग–बेड़ो पथ में बनई नदी पर पुल।

जहाँ आरओबी पर काम शुरू हैः-

- राँची–हटिया, राँची–पिस्का, सिमुलतल्ला–जसीडीह, कालुबथान–थापड़नगर, ढ़ोकड़ा–धनबाद, पारसनाथ–चेरगो, कुनकी–कांद्रा।

जिस पर काम शुरू होना हैः-

- धनबाद–भूली, राय–खलारी, भूती–तेतुलमारी, पाकुड़, डालटनगंज–कजरी, अमला–फुसरी, घाटशिला–गालुडीह।

शिक्षा की बुनियाद सुदृढ तथा गुणवत्ता में वृद्धि

- 48 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। पच्चीस हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति।
- नवम्बर 2000 से अब तक 30 लाख बच्चों का नामांकन।
- विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति निश्चित कराने हेतु, प्रति छात्र एक रूपया की दर से प्रोत्साहन राशि।
- मेधा छात्रवृति योजना शुरू। गृह अंचल में शिक्षकों का पदस्थापन। प्राथमिक एवं विद्यालयों मे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। झारखण्ड अधिविद्य परषिद की स्थापना। सी.वी.एस.ई. के अनुरूप पाठयक्रम लागू। 112 प्राथमिक विद्यालय, 12 राजकीय विद्यालय एवं 98 माध्यमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार। शिक्षा विभाग के रिक्त साढ़े तीन हजार माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू। राँची, हजारीबाग एवं दुमका विश्वविद्यालयों के लिए अपने परिसर के विकास हेतु राशि उपलब्ध। नीलाम्बर पीताम्बर तथा राष्ट्रीय विधि ा विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू। विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र नियमित। नया यू.जी.सी. वेतनमान लागू एवं वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति।

स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता

- राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य tul[;k uhfr] LokLF; uhfr vkj vk"kf/k uhfr की घोषणा की गयी है। स्वास्थ्य नीति में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। औषधि में मरीजों को गुणवत्ता–युक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास ।

सहृदय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा

- इसके अतिरिक्त जनहित की सबसे कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के गरीब तथा असाध्य रोग से पीड़ित 1776 मरीजों को अनुदान के रूप में करीब 10 करोड़ से भी अधिक रूपये दिये। गुर्दा, हृदय, एड्स और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज को इलाज के लिए राज्य और राज्य के बाहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भेजा गया। प्रत्येक महीने में दो बार >kj[k.M jkT; chekjh lgk;rk fuf/k icU/ku lfefr की बैठकों में गरीब रोगियों के अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड पर्यटन को नई पहचान :-

- प्राकृतिक सौन्दर्य से डूबे हुए राज्य में पर्यटक स्थलों का जाल बिछाने के लिए कारगार प्रयत्न। अनेक योजनाएं शुरू की जा चुकी है। सरकार की यह कोशिश है कि पर्यटन के क्षेत्र में झारखण्ड देश और दुनिया में अपनी खास पहचान बनाकर उभरे। राँची के आसपास के साथ–साथ अन्य पर्यटन स्थलों कांके डैम, हटिया डैम, राँची हिल, टैगोर हिल, जगन्नाथ मंदिर, हुंडरू, दशम, तथा जोन्हा जल प्रपातों के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। देवघर मंदिर परिसर में 1.40 करोड़ की लागत से लाइट एवं साउंड शो क्रियान्वित किया जा रहा है। जमशेदपुर के डिमना लेक स्थल पर VfjLV dkEiyDl dk fuekZ.k] बोटिंग एवं अन्य पर्यटन सुविधाओं के लिए 212 लाख रूपए की योजना स्वीकृत की गयी है।

खनिज सम्पदाओं की मनमाने दोहन की समाप्ति : पूँजी निवेश का नया दौर शुरू :-

- राज्य बनने के बाद 27 खनिजों, जिसमें मख्यतः पाराक्जोनाइट, चाइनाक्ले, लाइम स्टोन, कोयला, सोना शामिल हैं, के लिए 700 से अधिक उद्यमियों को लीज पट्टा जारी किया गया हैं। कोल बेड मिथन के पांच ब्लॉक भी चिन्हित किये गये हैं। जिनमें से तीन ब्लॉक 519 वर्ग किलोमीटर और दो ब्लॉक 337 वर्ग किलोमीटर में है। इन्हें लीज पर देने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा सरकार ने राज्य की खनिज सम्पदा से दुनिया को परिचित कराने के भी प्रयास किये, ecbZ esa jkM 'kks किया। इन आकर्षक कार्यक्रमों के बाद अब तक 33 ns'kh&fons'kh m|fe;ksa dh 28390 djksM+ :i;s dh iw¡th fuos'k के प्रस्ताव दिये। विभिन्न खनिजों के उत्खनन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 8000 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश के प्रस्ताव खनिज आधारित उद्योगों के लिए तथा 7200 करोड़ रूपये के प्रस्ताव बाक्साइट आधारित उद्योग लगाने के लिए है।

- राज्य में कोल बेड मिथेन के 3 ब्लॉक्स यथा नार्थ कर्णपूरा बोकारो एवं झरिया के लिए पोट्रोलियम् एक्सप्लोरेशन् लाईसेंस निर्गत ।

- राज्य के खनिज क्षेत्र में देश–विदेश की कंपनियों द्वारा निवेश कराकर खनिज के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार बढ़ाना।

- राज्य में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम् से खनिज संपदा का पता लगाना ओर खनिजों का वैज्ञानिक दोहन।

- राज्य के खनिज क्षेत्रों में देश–विदेश की जानी–मानी कंपनियों द्वारा हजारों करोड़ का पूंजी निवेश के प्रस्ताव से झारखंड का विकास ।

- झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 द्वारा पत्थर व्यवसायियों तथा श्रमिकों को लाभ।

सूचना-तकनीकी को नए आयाम दिए :-

- विश्वसनीय सूचना के आदान प्रदान के लिए इंटरकनेक्टेड नॉड की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु झारनेट परियोजना पर तेजी से अमल तथा इसके तहत वॉयस डाटा, वीडियो कांफ्रेसिंग तथा अन्य सूचनाओं के बेहतर आदान–प्रदान की व्यवस्था की गई। सभी जिला मुख्यालयों में वीडियों कांफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके साथ ही स्पेश एप्लिकेशन सेन्टर, जैप आइ टी, फाइवर केवुल नीति, जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में वैज्ञानिक सोच उन्मुख करने के लिए ई–गवर्नेस की योजना, तारा मंडल राँची, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, साइन्स सिटी का निर्माण, सुपर मल्टी मीडिया कॉरिडोर, बोकारो, टेक्नोलोजी पार्क, चन्दन कियारी, बी.आई.टी सिन्दरी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की योजना, 30 प्रखंडो में सामुदायिक सूचना केन्द्र, >kj[k.M vkuykbu iksVZy dk fodkl] >kj[k.M e[;ea=h lwpuk iz.kkyh ifj;kstuk (जे सी एम आइ एस) जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं पर अमल।

हमें इन उपलब्धियों पर भी गर्व है : झारखण्ड विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर:-

- राज्य का विकास दर बढ़कर 5.61 प्रतिशत पर पहुँच गया । इस वर्ष के अंत तक यह करीब 7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है ।

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में 7 प्रतिशत से अधिक की कमी हुयी । बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ । 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया । इस वर्ष के अंत तक अतिरिक्त 40 हजार लोगों को केवल सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलने का अनुमान है ।

- वर्षों से लंबित स्वर्णरेखा जेसी महत्वाकांक्षी परियोजना से सिंचाई के लिए पानी देना शुरू हुआ । जीर्ण–शीर्ण पड़ी पुरानी सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत कर तथा चेकडैम, माइक्रोलिफ्ट, तालाब, कुँआ और जल छाजन के माध्यम से सिंचाई क्षमता में त्वरित वृद्धि की गयी । नतीजा हुआ कि राज्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ ।

- राज्य की कृषि नीति एवं कृषि विकास योजना तैयार करने के लिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में >kj[kM e! >kj[k.M d`f"k l|/kkj] 'kk/k ,o fodkl vk;kx गठित किया गया ।

- jkT; dh vk|kfxd uhfr तैयार की गयी । इसके आलोक में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम आरंभ हुआ । वर्षों से लंबित टाटा लीज का मामला काफी हद तक सुलझा लिया गया । राज्य को निर्माण गतिविधियों का केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयास शुरू हुआ।

- राज्य में fo'k"k vkfFkd tku स्थापित करने का निर्णय लिया गया । उद्योग क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपया से अधिक के पूंजी निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की कई कंपनियों से एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुआ । राज्य में रोजगारमुखी पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

- d`f"k fu;kr tku बनाने के लिए केन्द्र सरकार से सहमति प्राप्त की गयी। लघु उद्यागों, कुटीर उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार से मिलकर इन्हें वित्तीय एवं ढांचागत सहायता पहुँचाने तथा इनके उत्पादनों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास हुये । सक्षम निर्यात सुविधा तंत्र खड़ा करने के लिए ,;j dkxk LFkkfir करने का कार्य आरंभ हुआ।

- राज्य में सब्जी–फल–फूल तथा तसर का उत्पादन काफी बढ़ा । खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही परंपरागत जड़ी–बूटियों के प्रसंस्करण एवं अभिवृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाये गये, जिसका नतीजा जमीनी स्तर पर पूंजी निर्माण और किसानों एवं असंगठित क्षेत्र के हूनरमंद लोगों को सीधे लाभ के रूप में हुआ । ग्रामीण कुटीर क्षेत्रों में guj fodkl dsfy, i!f'k{k.k dk;Øe आरंभ किया गया ।

- सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के शत प्रतिशत बच्चों को शिक्षित करने का अभियान आरंभ हुआ । 10 हजार शिक्षकों की

नियुक्ति की गयी । राज्य में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया । वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की गयी । स्वरोजगार में सहायक व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई आरंभ की गयी । नामांकन के तुरंत बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 80 प्रतिशत से घट कर 50 प्रतिशत हो गई । अगले वर्ष यह संख्या शून्य हो जायेगी ।

- अनुसूचित वर्गों के कल्याण मद की राशि का उपयोग किया गया । अस्तित्व विहिन V!kbcy ,Mokbtjh dfeVh का गठन कर इसकी भूमिका बढ़ायी गयी । गरीबी रेखा से नीचे के जनजातीय युवकों के बीच स्वरोजगार के लिए बड़ी संख्या में बसें वितरित की गयी । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्र–छात्राओं के बीच 50 हजार से अधिक साईकिलें वितरित की गयी ।

- बी.आई.टी. मेसरा में पोलेटेकिनिक की स्थापना की गयी । राज्य के बाहर तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति एवं जाति के छात्रों के लिए क्रमशः fcjlk e|.Mk ,o vEcMdj rduhdh Nk=ofr ;kstuk आरंभ की गयी । इसके साथ ही सभी जिलों में आवासीय छात्रावासों का निर्माण किया गया तथा fcjlk e|.Mk vkokl ;kstuk आरंभ की गयी ।

- राज्य में सड़कों की स्थिति दुरूस्त की गयी । उच्च पथों को चार लेन बनाने की दिशा में कार्य आरंभ हुआ । राजपथों एवं पुल–पुलिया तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ । राज्य के हवाई अड्डों को दुरूस्त करने तथा साहेबगंज में गंगा पुल के निर्माण और वहां से हल्दिया बंदरगाह तक नौ–परिवहन सुविधा आरंभ करने की दिशा में प्रयत्न शुरू हुआ । पश्चिमी सिंहभूम से पाराद्वीप बन्दरगाह को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हुआ ।

- हजारीबाग और दुमका को बड़ी रेल लाईन से जोड़ने तथा राँची–लोहरदगा छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलकर इसे टोरी तक ले जाने के लिए राज्य और केन्द्र की संयुक्त योजना के अंतर्गत कार्य आरंभ हुआ । रेल लाईनों के उपर ओवरब्रिज और पहुँच पथ बनाने का कार्य तेजी से आरंभ हुआ।

- झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड तथा jkT; fo|r fu;ked vk;kx का गठन किया गया । राज्य में 52 पावर सबस्टेशन और और संचरण लाइन बनाने

का काम शुरू हुआ । राज्य के जीर्ण–शीर्ण पड़े ताप विद्युत घरों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुयी । ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना शुरू की गयी और lHkh xkoks es 2007 rd fctyh igqpkus dk लक्ष्य रखा गया ।

- शहरी, अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और पेयजल की समस्या दूर करने का सशक्त प्रयास आरंभ हुआ । 30 हजार से अधिक नये नलकूपों का निर्माण और 20 हजार से अधिक जीर्ण–शीर्ण पड़े नलकूपों का पुनर्स्थापन किया गया ।
- उग्रवाद की समस्या पर काबू पाने का सघन कार्यक्रम आरंभ हुआ । पुलिस बल को आधुनिक अस्त्र–शस्त्र तथा मजबूत वाहनों से सुसज्जित किया गया । ग्रामीणों में उग्रवाद के खिलाफ आत्मविश्वास और प्रतिरोध की भावना पैदा हुयी । उग्रवादी पीछे हटने के लिए मजबूर हुए । दुर्गम क्षेत्रों में उग्रवादियों के दर्जनों बैंकर ध्वस्त किये गये । कई दुर्दान्त उग्रवादी गिरफ्तार हुए । उनके आर्थिक स्रोतों पर प्रहार हुआ । साथ ही संगठित अपराध पर भी जोरदार हमला हुआ ।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित पुलिसबल के लिए उनके वेतन का 15 प्रतिशत रिमोट एलाउएन्स देने का निर्णय लिया गया।
- राज्य के योजना उदव्यय में भारी वृद्धि हुई । पूर्व के नगण्य योजना उदव्यय की जगह प्रतिवर्ष 2500 करोड़ से 3000 करोड़ रुपया के बीच योजना और विकास उदव्यय किया गया और इसके लिए संसाधन का जुगाड़ किया गया।
- खेल, युवा एवं संस्कृति विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल हुयी। राज्य में खेल प्रतिभा विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धाओं में lQy f[kykfM;ks dks vkfFkd ikRlkgu दिया गया । jkT; ljdkj dks 2007 ds ,f'k;kb [ksyks dh etckuh djus ds fy, puk x;k A प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास करने और पर्यटन के राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय नक्शे पर इन्हें समुचित स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
- प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त, सक्षम, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने के लिए पहले की नियमावलियों और मैनुअलों में परिवर्तन किया गया । सरकारी तंत्र की कार्यशैली में परिवर्तन के लिए ठोस एवं कठोर कदम उठाये गये । ई–गवर्नेस की दिशा में पहल आरंभ हुई ।

- इसी तरह वन एवं पर्यावरण, खनन एवं भूतत्व, नगर विकास, खाद्य आपूर्ति, श्रम नियोजन, सहकारिता एवं अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार ने चार वर्षों की अल्पअवधि में भी सराहनीय एवं उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है ।

5. आह्वान :-

झारखंड में फरवरी माह के 'लोकतांत्रिक उत्सव' के पावन अवसर पर एक राजनैतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षा है कि झारखंड के पौने तीन करोड़ जनता का असीम स्नेह भाजपा को ही मिले। आकांक्षा को अवसर में बदलने के लिए जनमत की आवश्यकता होती है। 'जनमत' जुटाने में भाजपा का एक–एक कार्यकर्ता प्राण–प्रण से लगा है। कौन नहीं जानता कि झारखंड का भविष्य किस दल के हाथों में सुरक्षित है? साथ ही लोग यह भी जानते है कि झारखंड का भविष्य किन हाथों में असुरक्षित है।

हमें सतर्कता बरतनी होगी। सावधान रहना होगा और जनता–जनार्दन को भी सावधान करना होगा। गुमराह करने का दौर शुरू हो गया है। हमें लोकतंत्र के सौदागरों से बचना होगा। मतपेटियाँ लूटकर, फर्जी मतदान कर 'जनमत' पर डाका डालने वालों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। आज आम नागरिकों में घबराहट इस बात को लेकर है कि यदि 'वे' आ गये तो राज्य में क्या होगा?

गत 14 वर्षो से बिहार की 'जनता' अराजकता और आतंक के गंभीर दौर से गुजर रही है। शासन में जो बैठे हैं वे ही अपराधियों के पनाहगारों के प्रमुख है। लेकिन कौन बोले? सच बोलने वालों को बदले की भट्ठी में झोंक दिया जाता है। 'अपराध' को सम्मानित और अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आतुर राजैनतिक दल बेशर्म बन चुके हैं। सत्ता की भूख के आगे कांग्रेस एवं राजद ने सभी मर्यादाओं में आग लगा दी है।

समय आ गया है, जब हम पहली बार झारखंड में अपने मतों से एक निर्वाचित सरकार का गठन करेंगे। लोकतंत्र की पतवार पवित्र हाथों में सौंपने की महती जिम्मेदारी ईश्वर ने झारखंड के लगभग दो करोड़ मतदाताओं को सौंपी है। पिछले चार वर्षों पर एक नजर जरूर दौड़ा लें। एक नही अनेक जनहित के कार्य झारखंड की भजपा सरकार ने किये हैं। आभी और काम करना है। झारखंड को भारत के मानचित्र पर मान–सम्मान मिले और झारखंड एक ''आदर्श'' राज्य के रूप में स्थापित हो, यह प्रत्येक झारखंडवासियों के मन की बात है। सभी के मन की बात

पूरी तब होगी जब झारखंडवासियों का एक–एक मत भाजपा एवं जद(यू) के प्रत्याशियों को सभी क्षेत्रों में मिलेगा। नवम्बर 2000 में हमें मिला था एक खाली चित्रपट और एक कुशल कलाकार की तरह हमें पहले तस्वीर की कल्पना करनी थी, फिर रेखायें खींचनी थी रेखाओं में संतुलन बनाना था, उपयुक्त रंगों को चुनना था, उन्हें आवश्यकतानुसार अर्थात सम्पूर्ण सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए भरना था, एक नया झारखंड बनाना था, एक नई तस्वीर गढ़नी थी। स्वाभाविक है कि इस रचना के क्रम में कुछ रेखाओं को बनाकर मिटाना पड़ा, छोटी रेखाओं को थोड़ा बड़ा, बड़ी रेखाओं को थोड़ा छोटा करना पड़ा। चमन को सींचने में ऐसा होता है। हम कह सकते हैं कि

peu dk lhpu e
ifÙk;k dN >M xbl gkxh]
;gh bytke g ge ij
peu l ccQkbl dkA
ftUgkus jkn Mkyh f[kyrh dfy;k
viu ijk lA
ogh djr g nkok
bl peu d jguekbl dhA

यही निर्माण की स्वाभाविक प्रक्रिया है मित्रो! जिससे खुद विधाता को भी गुजरना पड़ता है। मगर हमारा संकल्प दृढ़ था, ध्येय जनहितों की निष्ठा से लबालब भरा था। पिछले चार साल का समय तो एक प्रकार से संक्रमण काल की तरह था परन्तु झारखंड का एक–एक व्यक्ति इस संक्रमण में हमारे साथ रहा, इस हेतु हम सभी के आभारी हैं।

हमें मात्र चार वर्ष काम करने का मौका मिला। हमने जो किया, उसे भी घोषणा–पत्र में हमने प्रस्तुत किया है। हम आगे जो करेंगे, उसे भी जनता–जर्नादन तक भावी संकल्प के रूप में पहुँचा रहे हैं। हो सकता है कि हम सभी मोर्चो पर खरे नहीं उतरें होंगे, पर हम यह बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी नीयत पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं कर सकता। हमारी नीयत झारखंड के विकास और समृद्धि के साथ सदैव से जुड़ी हुई है। हमारे खून का एक–एक कतरा झारखंड के विकास गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा के शीर्षस्थ नेता, देश के

करोड़ो लोगों के श्रद्धा पात्र प्रखर राष्ट्रभक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत के नक्शे पर झारखंड को राज्य की पहचान दी। झारखंड की नींव डाली। झारखंड के इस नींव में भाजपा के एक–एक कार्यकर्त्ता का समर्पण है।

अतः आपका हार्दिक सहयोग भाजपा प्रत्याशियों को 3, 15, एवं 23 फरवरी सन् 2005 को होने वाले राज्य के विधान सभा चुनाव में मिले।

भाइयों एवं बहनों! हम झारखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए हाथ में तूली और रंग लिए बैठे हैं। आप हमें अगले पांच वर्षों का नया जनादेश दें, जिससे हम एक–एक रेखा में उसके अनुरूप रंग भर कर आपकी अभिलाषा के अनुरूप खुशहाल झारखंड की तस्वीर को संपूर्णता प्रदान कर सकें।

^^gj ukjh dk lEeku
gj fiNM dk mRFkku
gj cPp dh i<kbl
gj jkxh dk nokbl
gj [kr dh flpkbl
ugh c<u nx egxkbl
xjhck dh c<xh dekbl
ij lekt dh gkxh Hkykbl
vkvkA ge lc feydj
ltk,&lokj >kj[kM dk Hkkbl**

t; Hkkjr

t; >kj[kM

>kj[k.M insk Hkkjrh; turk ikVhl }kjk idkf'kr rFkk
vUui.kkl il ,.M ikllsl] jkph e efnr@l@1000 ifr